एक महामारी का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

लेखक- रघुवीर श्रीनिवासन (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

21 मार्च, 2020

"ऐसे कई उपयोगी कार्रवाइयाँ हैं जिन्हें सरकार पूरे सेक्टरों में व्याप्त संकट से निपटने के लिए उपयोग में ला सकती है।"

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए मजबूत उपायों का प्रभाव अर्थव्यवस्था के स्तर पर महसूस किया जाने लगा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि महामारी के आर्थिक प्रभाव का आकलन करने और कारगर उपायों का सुझाव देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

टास्क फोर्स पर चर्चा के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं।

नकद हस्तांतरण

कैब ड्राइवर, रेस्तरां वेटर, मॉल वर्कर, घरों में काम करने वाले, इटरनेन्ट रिटेलर्स और अन्य कैजुअल जॉब वर्कर्स जैसे लोग या तो पहले से ही जॉब और इनकम के बिना हैं या जल्द ही खुद को उस स्थिति में पाएंगे।

इन कमजोर वर्गों के लिए एक निश्चित राशि के नकद हस्तांतरण पर विचार करना एक बुरा ख्याल नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 33 करोड़ खाते हैं जिन्हें इस उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। अधिकांश राज्यों में एक कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी प्रचलित है जिसके माध्यम से लाभार्थियों की पहचान नकदी के लिए की जा सकती है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल के अनुसार देश में कुल 23.53 करोड़ राशन कार्ड हैं। यह मानते हुए कि ये सभी गरीबी रेखा कार्ड से नीचे हैं, 1,000 का स्थानांतरण, जो कि सबसे कम है और जिस पर विचार किया जाना चाहिए। इससे केंद्र सरकार पर 23,500 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा।

पिछले महीने, हांगकांग ने एक सहायक उपाय के रूप में हर स्थायी निवासी को 10,000 हांगकांग डॉलर नकद देने की घोषणा की। संयुक्त राज्य अमेरिका भी अपने नागरिकों को कुल 250 बिलियन डॉलर के नकद भुगतान का विकल्प दे रहा है।

ऋण की गारंटी

एयरलाइन, होटल और रेस्तरां और पर्यटन जैसे सेवा उद्योगों को मंदी एहसास होने लगा है और निश्चित रूप से यह समस्या विनिर्माण क्षेत्र में भी विस्तारित होगा।

बैंक स्पष्ट रूप से इन व्यवसायों को बैड लोन के साथ अपने स्वयं के मुद्दों को देखते हुए कोई मदद नहीं करने जा रही है। यह वह जगह है जहाँ सरकार इस बात पर विचार कर सकती है कि पश्चिम के अधिकांश प्रभावित देशों ने प्रभावित व्यवसायों के लिए ऋण की गारंटी दी है। ब्रिटेन ने 330 अरब डॉलर के सरकार समर्थित ऋण और गारंटी का वादा किया है, फ्रांस और स्पेन ने क्रमशः € 300 बिलियन और € 100 बिलियन सहायता की घोषणा की है।

यह प्राथमिकता व्यवसायों को लिक्विडेट (liquidate) रखना है और यही कारण है कि इन देशों ने गारंटी के रूप में इतनी बड़ी मात्रा प्रदान की है। इन मुश्किल समय में कैश मशीन को बेहतर रखना पड़ता है और सरकार इसमें भूमिका निभा सकती है। एक शुरुआत के लिए यह कार्यशील पूँजी ऋण की गारंटी प्रदान कर सकता है और इसे संबंधित उधारकर्त्ताओं को आश्वासन के साथ जोड़ सकता है कि वे अपनी कंपनियों में रोजगार को सुरक्षित करेंगे।

एक समान मासिक किस्त (EMI) पर छूट व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए एक बड़ा आशीर्वाद हो सकती है वो भी उस समय जब नौकरी की हानि, वेतन में कटौती या राजस्व की हानि का सामना करना पड़ रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष जब बात उद्योगों की आती है तो बैंकों के लिए परिसंपत्ति मान्यता के मामले में विनियामक संयम दिखाना चाहिए। लेकिन यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह केवल अस्थायी चोट है, एक बार संकट से बाहर होने पर स्थिति फिर उसी समान हो जाएगी।

भगवान न करें, लेकिन अगर यह बंद अगले कुछ हफ्तों से आगे बढ़ता है, तो सरकार को व्यवसायों को अस्थायी कर राहत प्रदान करने की ओर देखना होगा। हम एक अभूतपूर्व स्थिति देख रहे हैं, जहाँ राजस्व नीचे गिर सकता है और नकदी प्रवाह शून्य से नीचे जा सकती है। ऐसे अन्य सहायक कार्यवाइयाँ हैं जिसे सरकार अपना सकती है, जैसे अपने बिलों का तुरंत निर्वहन करते हुए बिना देरी के करों को वापस करते हुए और यदि आवश्यक हो तो प्रभावित व्यवसायों को अस्थायी रूप से भविष्य निधि और ईएसआई जैसे सांविधिक बकाये के भुगतान में छूट की अनुमति दे सकता है।

कैसे करें वित्त प्रबंधन?

यह कठिन है लेकिन इसका उत्तर व्यवहार्य है। इस आर्थिक त्रासदी के प्रति राष्ट्रीय प्रतिक्रिया विकसित करने के लिए केंद्र और राज्यों के संसाधनों को तैयार करना होगा। उदाहरण के लिए, केरल ने पहले ही 20,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा कर दी है और अन्य राज्य भी इसी तरह पालन कर सकते हैं। केंद्र के लिए राज्य संसाधनों का लाभ उठाने के लिए यह एक अच्छा विचार हो सकता है।

दूसरा, सरकार को सहायता उपायों को सुनिश्चित करते हुए निजी क्षेत्र के साथ जुड़ना होगा। निजी क्षेत्र में बहुत सारी विशेषज्ञता उपलब्ध हैं। वायरस ने एक महीने के पुराने बजट को अव्यवस्थित कर दिया है, जिसके कारण इसकी संख्या अब अवास्तविक प्रतीत होती है। केवल कर राजस्व ही नही है जो परेशानी का विषय बन रहा है, यहाँ तक कि 2.10 लाख करोड़ का विनिवेश बजट भी अब पहुँच से बाहर प्रतीत हो रहा है। इस पृष्ठभूमि में, बजट के लिए अब किसी भी प्रोत्साहन कार्यक्रम को निधि देना असंभव है। अतिरिक्त बजटीय समर्थन की आवश्यकता होगी और यही वह जगह है जहाँ एक बॉन्ड मुद्दे का विचार आता है।

एक अच्छी तरह से संरचित, कर-कुशल बॉन्ड मुद्दा घरेलू बचत के बड़े पूल में शामिल करने का एक विकल्प हो सकता है। बड़े भारतीय प्रवासी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हमें 1998 के पोखरण के रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स के अनुभव को याद करना चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक ने प्रतिबंधों के तत्काल प्रभाव से भारत को निजात दिलाने के लिए सभी बाधाओं के खिलाफ अनिवासी भारतीयों से लगभग 4 बिलियन डॉलर जुटाए थे। तो सवाल उठता है कि अब ऐसा कुछ क्यों नहीं हो सकता?

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. भारत पर कोरोना वायरस के प्रभावों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसके कारण प्राइवेट फर्म में काम करने वाले लोगों को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ सकता है।
2. इससे केन्द्र सरकार को अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ सकता है।
3. गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कोरोना वायरस के प्रभावों का आकलन करने के लिए एक टास्क फोर्स गठन किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements in the context of the effect of corona virus on India:

1. Due to this people working in private firm may face unemployment.
2. This may lead to additional expenditure to the Central Government.
3. A task force has been formed under the headed by the Home Minister Amit Shah to assess the effects of corona virus.

Which of the above statements is / are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) 1 and 2 (d) 1, 2 and 3

नोट : 20 मार्च को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. कोरोना वायरस के महामारी के रूप लेने और उसके आर्थिक दुष्प्रभावों से लड़ने में भारत सरकार के प्रयासों और उनके समक्ष उपस्थित चुनौतियों की चर्चा करें। (250 शब्द)

Discuss the efforts and challenges in front of Government of India in tackling the development of corona virus into a pandemic and its economic side effects. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।